दैनिक जागरण

दया ही श्रेष्ठ धर्म है

# पाकिस्तान का ढोंग

पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान के इस कथन को महत्व न देने में ही समझदारी है कि भारतीय प्रधानमंत्री शांति को एक अवसर और दें। यह अपील करते हुए इमरान ने जिस तरह यह कहा कि अगर भारत पुलवामा हमले में कार्रवाई योग्य खुफिया जानकारी उपलब्ध कराता है तो उस पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी, उससे यह स्पष्ट हो जाता है कि वह भारत के साथ दुनिया की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वह भारत का भरोसा जीतने के तनिक भी इच्छुक हैं तो सबसे पहले उन्हें जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर को गिरफ्तार करना चाहिए। इसके अलावा उन्हें पठानकोट हमले में इसी आतंकी सरगना और उसके भाई के हाथ होने के संबंध में भारत की ओर दिए गए सुबूत भी देखने चाहिए। उन्हें मुंबई हमले की साजिश रचने वाले आतंकियों के खिलाफ भी कुछ करना चाहिए, क्योंकि 11 साल बीत जाने के बावजूद वे पाकिस्तान में न केवल छुट्टा घूम रहे हैं, बल्कि भारत के खिलाफ आग भी उगल रहे हैं। इमरान को इससे भी परिचित होना चाहिए कि भारत में वांछित एक अन्य आतंकी सरगना दाऊद इब्राहिम भी कराची में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के संरक्षण में पल रहा है। आखिर वह किस मुंह से अमन को एक और मौका देने की मोहलत मांग रहे हैं?

इमरान खान ने पुलवामा हमले के पीछे जैश ए मोहम्मद का हाथ होने के सुबूत जिस तरह भारत से मांगे उससे यही पता चलता है कि उनके नेतृत्व में तथाकथित नया पाकिस्तान भी उसी पुराने ढर्रे पर ही चल रहा है जिसके तहत पहले भारत से सुबूत मांगे जाते हैं और फिर उन्हें अपर्याप्त बता दिया जाता है। पाकिस्तान अपनी सेना और उसकी खुफिया एजेंसी के इशारे पर काम करने वाली अपनी अदालतों की स्वतंत्रता का गुण गाते हुए यह बहाना भी खूब बनाता है कि वे अपना काम कर रही हैं। क्या यह मजाक नहीं कि ओसामा बिन लादेन का सुराग देने वाले पाकिस्तानी डॉक्टर को तो वहां की अदालतों ने आनन-फानन सजा सुना दी, लेकिन मुंबई हमले की साजिश रचने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने का दिखावा भी नहीं कर पा रही हैं? आखिर यह भारत को धोखा देने के साथ आतंक को संरक्षण देने की पाकिस्तानी फितरत नहीं तो और क्या है? आतंकी संगठनों पर पाबंदी लगाने का ढोंग करना भी उसकी फितरत है। इमरान खान कहें कुछ भी, उन्होंने अपने रवैये से इसी धारणा को गहराया है कि पाकिस्तान भारत के लिए खतरा बने आतंकी संगठनों को पालने-पोसने से बाज आने वाला नहीं है। निःसंदेह केवल इतना ही पर्याप्त नहीं कि भारत इमरान की अपील को गौर करने लायक नहीं मान रहा है। जरूरी यह भी है कि भारतीय नेतृत्व यह देखे कि पाकिस्तान पर चौतरफा दबाव कैसे डाला जाए? पाकिस्तान फिलहाल भारत के रवैये और अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया से सहमा अवश्य है, लेकिन वह इसी ताक में दिख रहा कि विश्व समुदाय के दबाव से कैसे मुक्त हुआ जाए। हैरत नहीं कि इसी कोशिश के चलते इमरान ने शांति को एक और मौका देने का शोशा छोड़ा हो। भारत यह ध्यान रखे तो बेहतर कि पाकिस्तान आसानी से बदलने वाला नहीं।

# चुनावी तैयारी

लोकसभा चुनाव अब महज कुछ ही हफ्ते दूर हैं तो सियासी पार्टियां पूरी शिद्दत से अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुट गई हैं। उत्तराखंड के अलग राज्य बनने से पहले भी यहां भाजपा और कांग्रेस का ही वर्चस्व रहा और राज्य गठन के बाद भी यही सिलसिला जारी है। लोकसभा और विधानसभा चुनाव में कभी एक पार्टी का पलड़ा भारी रहता है तो कभी दूसरी। राज्य गठन के बाद इतना अंतर जरूर आया कि बसपा उत्तराखंड में तीसरी सबसे बड़ी सियासी ताकत के रूप में उभरी। राज्य के पहले दो विधानसभा चुनाव में तो बसपा सात से आठ सीटें हासिल करने में कामयाब रही। तीसरे विधानसभा चुनाव में यह आंकड़ा तीन सीटों तक सिमट गया, जबकि नमो लहर में हुए चौथे विधानसभा चुनाव में बसपा खाली हाथ रह गई। वर्ष 2017 में हुए इस चुनाव में 70 सदस्यों वाली विधानसभा में भाजपा अकेले 57 सीटों पर काबिज हुई, जबकि कांग्रेस को केवल 11 सीटों पर सिमटना पड़ा। जहां तक सपा का सवाल है, अब तक के चार विधानसभा चुनावों में उसे एक भी सीट हासिल नहीं हो पाई है। अलबत्ता वर्ष 2004 के लोकसभा चुनाव में सपा ने हरिद्वार सीट पर परचम फहराया था। यह सपा की उत्तराखंड में अब तक की एकमात्र चुनावी जीत रही है। आगामी लोकसभा चुनाव में जरूर भाजपा और कांग्रेस को चुनौती पेश आ सकती है। उत्तर प्रदेश में सपा-बसपा में चुनावी गठबंधन के बाद यह तय माना जा रहा है कि उत्तराखंड में भी दोनों पार्टियां मिलकर ही चुनाव लड़ेंगी। कम से कम दो लोकसभा सीटों हरिद्वार और नैनीताल को इस लिहाज से सपा-बसपा के लिए मुफीद माना जा सकता है। इन दो सीटों पर दोनों पार्टियों का ठीकठाक वोट बैंक है। अब अगर इन दो पार्टियों के बीच उत्तर प्रदेश की तर्ज पर उत्तराखंड में भी गठबंधन हुआ तो नैनीताल एवं हरिद्वार लोकसभा सीटों पर ये मुकाबले को दिलचस्प शक्ल दे सकते हैं। हालांकि यह कहना अभी जल्दबाजी होगी कि संभावित गठबंधन का नफा-नुकसान भाजपा और कांग्रेस में से किसे होगा, लेकिन इतना जरूर है कि इससे चुनावी महासमर का परिदृश्य इस बार पहले की अपेक्षा कुछ बदला हुआ नजर आएगा।

# खत्म किया जाए सिंधु जल समझौता

डॉ. भरत झुनझुनवाला

**सिंधु जल समझौते को हमने सद्भाव एवं मित्रता के आधार पर किया था। जब यह सद्भाव और मित्रता ही नहीं रही तो इस समझौते का आधार ही समाप्त हो जाता है**

पुलवामा आतंकी हमले के जवाब में सैन्य कार्रवाई के हमारे विकल्प सीमित दिखते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के पास भी परमाणु अस्त्र हैं। कोई भी सैन्य कार्रवाई परमाणु युद्ध में बदल सकती है जो दोनों देशों पर बहुत भारी पड़ेगी। पुलवामा के बाद भी पाकिस्तान द्वारा भारतीय सरहद के भीतर गोलाबारी जारी है। लगता है कि पाकिस्तान भारत की विवशता को समझ रहा है कि हम सैन्य कार्रवाई नहीं कर सकेंगे और हमारी इस मजबूरी का लाभ उठा रहा है। इस परिस्थिति से निपटने के लिए भारत सरकार ने पाकिस्तान की आर्थिक मोर्चेबंदी की रणनीति अपनाई है। पाकिस्तान से आयात होने वाली सभी वस्तुओं पर 200 प्रतिशत का आयात कर लगा दिया है जिसके कारण पाकिस्तान से कोई भी आयात संभव नहीं होगा, मगर पाकिस्तान द्वारा भारत को किए जाने वाले निर्यात उसके कुल निर्यातों का मात्र 1.4 प्रतिशत हैं। पाकिस्तान भारत को मुख्य रूप से सीमेंट फलों का निर्यात करता है। ऐसा नहीं कि ये वस्तुएं केवल भारत को ही निर्यात होती हैं। ऐसे में पाकिस्तान इन्हें दूसरे देशों को निर्यात करने का रास्ता निकाल लेगा। हालांकि फलों को फौरी तौर पर दूसरे देशों में निर्यात करने में जरूर कुछ मुश्किलें आ सकती हैं। इससे किसानों को घरेलू मंडी में माल बेचना होगा, घरेलू बाजार में फल के दाम कम होंगे और घरेलू खपत बढ़ेगी। जैसे किसान का दूध बिकना कम हो जाए तो घर के बच्चों को दूध अधिक मिलता है। इसका पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा, परंतु संकट जैसी स्थिति पैदा नहीं होगी। इसलिए आयात कर की इस वृद्धि का पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर कोई विशेष प्रभाव पड़ने की संभावना कम ही है।

हालांकि पाकिस्तान की वित्तीय हालत पहले से ही खराब है, लेकिन इस कमजोर वित्तीय स्थिति से भी पाकिस्तान टूटेगा नहीं। चीन और सऊदी अरब ने पाकिस्तान को धन उपलब्ध करा दिया है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष भी पाकिस्तान को धन उपलब्ध कराने को तैयार है। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस हाल में भारत आए थे। उन्होंने आतंकवाद के विरोध में कुछ बातें जरूर कहीं, लेकिन पाकिस्तान का नाम नहीं लिया जो कि उनके पाकिस्तान के समर्थन को ही दर्शाता है। ऐसे हालात में हमें सिंधु जल समझौते को निरस्त करने पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। पाकिस्तान के पास कुल 1450 लाख एकड़ फुट नदी का पानी उपलब्ध है। 1 लाख एकड़ फुट का अर्थ हुआ एक एकड़ भूमि पर एक फुट जितना पानी उपलब्ध हो। इस 1450 लाख एकड़ फुट जल में 1160 लाख एकड़ फुट पानी सिंधु, झेलम और चिनाब नदियों से पाकिस्तान को मिलता है जो कि भारत से होकर ही बहती हैं। वर्षा के पानी को छोड़ दें तो नदियों से मिलने वाले पानी का अस्सी प्रतिशत पानी पाकिस्तान को भारत से मिलता है। यही पानी सर्दी और गर्मी में पाकिस्तान की कृषि, उद्योगों और शहरों के काम आता है। यदि हम इस पानी को रोक लें तो पाकिस्तान को जल्द ही घुटने टेकने पड़ सकते हैं, लेकिन ऐसा करने में भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ सिंधु जल समझौता आड़े आता है। इसका भी रास्ता उपलब्ध है।

अवधेश राजपूत

सिंधु जल समझौते की प्रस्तावना में लिखा गया है कि भारत और पाकिस्तान ने इस समझौते पर सद्भाव और मित्रता के आधार पर दस्तखत किए हैं। कानून के जानकारों के अनुसार किसी भी कानून को समझने के लिए उसकी प्रस्तावना को देखना पड़ता है कि उसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य के अनुसार ही कानून का विवेचन होता है। सिंधु जल समझौते को हमने सद्भाव एवं मित्रता बनाए रखने के लिए किया था। जब यह सद्भाव और मित्रता ही नहीं रही तो सिंधु जल समझौते का आधार ही समाप्त हो जाता है। हमें इसे निरस्त करने में कोई हिचक नहीं होनी चाहिए। यह सही है कि समझौते में लिखा है कि इसमें कोई भी परिवर्तन आपसी समझौते से ही किया जाएगा, लेकिन जब समझौता ही रद हो जाए तो उसमें किए गए प्रावधानों का कोई मतलब नहीं रह जाता। जैसे भारत के स्वतंत्र होने पर ब्रिटिश राज्य द्वारा बनाए गए नियमों एवं कानूनों का कोई औचित्य नहीं रह गया। मान लीजिए आपने किरायेदार से समझौता किया कि वह दीवार पर कुछ नहीं लिखेगा। इस समझौते का कोई वजूद नहीं रह जाता यदि किरायेदार ने आपका घर ही खाली कर दिया।

सिंधु जल समझौते में यह व्यवस्था भी है कि मतभेद होने पर विश्व बैंक की मध्यस्थता की जाएगी। ध्यान दें कि मध्यस्थता का अर्थ साथ में वार्ता करना मात्र होता है। विश्व बैंक न तो निर्णय दे सकता है, न ही कोई पक्ष विश्व बैंक की सलाह मानने को बाध्य है। फिर भी इस प्रावधान के तहत हम विश्व बैंक को नोटिस दे सकते हैं कि एक सप्ताह के भीतर यदि पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद समाप्त नहीं हुआ तो हम इस समझौते को रद कर देंगे। इसके लिए हमें अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से भी सीख लेनी चाहिए जिन्होंने मेक्सिको और कनाडा से हुए मुक्त व्यापार समझौतों को एक चुटकी में निरस्त कर दिया। इसी प्रकार हमें भी सिंधु जल समझौते को निरस्त करने पर विचार करना चाहिए।

एक और विषय यह है कि चंद जिहादी लोगों ने पूरी दुनिया को कैसे भयाक्रांत कर रखा है? फिर चाहे वह अमेरिका में वर्ल्ड ट्रेड टावर पर हुआ हवाई हमला या हाल का पुलवामा आतंकी हमला। उनकी ताकत दर्शाती है कि इस्लाम में जिहाद के आंतरिक और वाह्य पक्ष दोनों एक साथ चलते हैं। न्यू वर्ल्ड इनसाइक्लोपीडिया के अनुसार जिहाद के अंतर्गत मुसलमानों की जिम्मेदारी बनती है कि वे आध्यात्मिक विकास के लिए आंतरिक युद्ध और इस्लाम के प्रसार के लिए बाहरी युद्ध दोनों करें। ऐसा करने से जिहादी युवक के मानस में आंतरिक ऊर्जा और इस्लाम के विकास के लिए बाहरी कार्य का जुड़ाव हो जाता है। जब जिहादी लड़ाका आत्मघाती हमला करता है तो उसे विश्वास रहता है कि वह जन्नत में जाएगा और इस्लाम का विस्तार भी करेगा। इसलिए उन्हें इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देने में तनिक भी संकोच नहीं होता है।

इसके विपरीत हिंदू और बौद्ध धर्म में आंतरिक और बाहरी युद्धों को अलग-अलग किया गया है। हिंदू धर्म में निवृत्ति और प्रवृत्ति दो भिन्न मार्ग बताए गए हैं। बौद्ध धर्म में हीनयान और महायान दो अलग-अलग मार्ग बताए गए हैं। इस अलगाव का अर्थ यह हुआ कि जब हिंदू युवक बाहरी कार्य करता है तो उसे मानस की आंतरिक ऊर्जा से जुड़ना अनिवार्य नहीं होता। यदि हिंदू युवक पाकिस्तान में प्रवेश कर आतंकवादी बने तो उसे कोई आंतरिक लाभ नहीं मिलेगा। हमारे युवक अपेक्षा करते हैं कि आंतरिक ऊर्जा से लैस पाकिस्तानी युवकों का सामना भारतीय सेना करेगी, न कि वे स्वयं। हमें इस समस्या का हल निकालना होगा। हमें अपने वैचारिक दृष्टिकोण में बदलाव लाने का प्रयास करना चाहिए और निवृत्ति और प्रवृत्ति को जोड़कर एक साथ करना चाहिए जिससे हम आतंकवाद का सामना कर सकें। हिंदू और बौद्ध धर्मों के सामने असल चुनौती इस्लाम की नहीं, बल्कि इस आंतरिक सुधार की है।

(लेखक वरिष्ठ अर्थशास्त्री एवं आइआइएम बेंगलुरु के पूर्व प्रोफेसर हैं)

response@jagran.com

# मनरेगा से बेहतर किसान सम्मान योजना

आशुतोष झा

**मनरेगा में काम कर रहे लोग करीब चार-पांच करोड़ ही हैं, जबकि किसान योजना के दायरे में 12 करोड़ किसान हैं**

पीएम किसान सम्मान निधि योजना देश में औपचारिक रूप से लागू हो गई है और लगभग एक करोड़ किसानों के खाते में दो हजार रुपये की पहली किस्त पहुंच चुकी है। इस महीने के अंत तक लगभग दस करोड़ किसानों तक यह राशि पहुंच जाएगी। संभवतः चुनाव के बीच ही खरीफ सीजन से पहले और आखिर में रबी सीजन से पहले दो किस्त और पहुंचेंगी। यानी 12 करोड़ किसानों को साल में छह हजार रुपये। देश में किसानों की आर्थिक स्थिति को देखते हुए यह बहुत छोटी-सी राशि लग सकती है और खासकर तब जब कांग्रेस अध्यक्ष घूम-घूमकर इसका उपहास उड़ा रहे हों और बता रहे हों कि यह तो सिर्फ 17 रुपये प्रतिदिन की योजना है। उनकी मानें तो वह किसानों की एकमुश्त कर्ज माफी करना चाहते हैं। चुनावी साल में ऐसे आरोप-प्रत्यारोप और एक-दूसरे से बढ़-चढ़कर वादे लाजिमी हैं, लेकिन अगर पहली संप्रग सरकार की चुनाव जिताऊ योजना मनरेगा से इसकी तुलना की जाए तो जो आंकड़े आएंगे उससे शायद राहुल गांधी भी चौंक जाएं। यह सवाल भी उठेगा कि क्या उनके सलाहकारों ने इस योजना की पूरी व्याख्या कर उन्हें बताई? सच्चाई यह है कि 2008-09 की मनरेगा कम से कम आंकड़ों और गरीबों को मिल रहे फायदे के बाबत 2018-19 की किसान योजना से पीछे थी। सच्चाई यह है कि 12 साल पहले लागू हुई मनरेगा आज भी दायरे में पीएम किसान योजना से छोटी है। ऐसे में कांग्रेस जैसी पुरानी पार्टी से यह जरूर अपेक्षा की जाएगी कि वह किसान सम्मान निधि योजना का उपहास उड़ाने से पहले तथ्यों की पूरी तहकीकात कर ले।

जिस सामान्य गणित से कांग्रेस अध्यक्ष ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना को 17 रुपये प्रतिदिन की योजना करार दिया है उसी आधार पर मनरेगा का आकलन किया जाना चाहिए। मनरेगा भले ही वर्ष 2006 में शुरू हुई थी, लेकिन पूरे देश में यह चुनावी साल 2008-09 में पहुंची थी। इसमें यह गारंटी दी गई थी कि ग्रामीण मजदूरों को साल में सौ दिन रोजगार मिलेगा और संबंधित राज्य की न्यूनतम मजदूरी को ही वहां मान्य बनाया गया था। इस आधार पर देश के अलग-अलग राज्यों में मजदूरों को 60 रुपये से लेकर 200 रुपये तक मिलना शुरू हुआ था। इतनी मजदूरी उनके लिए थी जो आठ घंटे का पूरा काम करते थे और जिनका काम कम हुआ उसकी मजदूरी कटती थी, लेकिन यह उल्लेखनीय है कि 100 दिन की गारंटी के बावजूद पूरे देश में जरूरतमंद लोगों को औसतन 50 दिन से भी कम का रोजगार मिला। रोजगार का यह आंकड़ा मनरेगा आज तक पार नहीं कर पाया, बल्कि धीरे-धीरे यह आंकड़ा घटता जा रहा है। खैर उस आधार पर वर्ष 2008-09 में मजदूरों को सालाना औसतन लगभग

चार हजार रुपये ही मिल पाए थे। यह बताने की जरूरत नहीं कि उस चार हजार रुपये को पूरे साल की रोजाना आय में बांटा जाए तो मजदूरों के हाथ जो आया वह महज 11 रुपये के आसपास था। दूसरी तरफ पीएम किसान सम्मान निधि योजना में सीमांत और लघु किसानों को सालाना छह हजार रुपये की गारंटी है। कोई किंतु परंतु नहीं, कोई बिचौलिया नहीं। कोई भ्रष्टाचार नहीं, क्योंकि यह पैसा सीधे किसानों के खाते में पहुंच रहा है। मनरेगा पर सीएजी रिपोर्ट ने बताया था कि लंबे अरसे तक किस तरह मजदूरों के खाते में पैसे चढ़े जरूर, लेकिन गया बिचौलियों की जेब में। आज भी मनरेगा योजना चल रही है। अब इसके तहत राशि भी बढ़कर लगभग 60 हजार करोड़ रुपये हो गई है, जॉब कार्ड भी दस करोड़ के आसपास हैं, लेकिन काम कर रहे लोगों की संख्या चार-पांच करोड़ के ही आसपास है, जबकि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के दायरे में 12 करोड़ किसान हैं। जाहिर है दायरे में पहले दिन से ही किसान योजना मनरेगा से तीन गुना बड़ी है। मनरेगा से जुदा पीएम किसान योजना में पूरे देश के किसान एक जैसे लाभान्वित होंगे। मनरेगा में यह विषमता बरकरार है। उद्योगीकरण में पिछड़े पूर्वी राज्यों के मजदूरों को मनरेगा में दक्षिण के मुकाबले आधी से कम राशि मिलती है।

मनरेगा अपने समय की अनोखी योजना थी। इसे प्रभावी बनाने के लिए तत्कालीन ग्रामीण विकास मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह को सरकार के अंदर तीखी लड़ाई लड़नी पड़ी थी। इस योजना ने बहुत कुछ बदला। जब काम न हो तो काम देना और घर के पास ही काम मिलना। यही कारण है कि लाख गड़बड़ियों और छोटे दायरे के बावजूद मनरेगा को चुनाव में गेम चेंजर माना गया। पीएम किसान योजना का राजनीतिक प्रभाव क्या होगा, यह तो वक्त बताएगा, लेकिन गरीबों की हालत में बदलाव की मंशा वही है। दो-दो हजार रुपये की तीन बार मदद तब जबकि बुआई का वक्त हो। इस पर बहस हो सकती है कि क्या यह राशि थोड़ी और बढ़नी चाहिए थी? लेकिन फिलहाल इससे इतनी-सी मदद जरूर हो जाएगी कि खेत में बीज पड़ जाएं। बीज बोने से पहले ही साहूकार के पास फसल गिरवी न रखनी पड़े। यह भी ध्यान रखना चाहिए कि बड़ी संख्या में सीमांत किसान बैंकों के कर्जदार नहीं, बल्कि साहूकारों के दबाव में हैं। लगभग 60 फीसद किसान सीमांत होते हैं और इन्हें चुनावी साल में मिलने वाली कर्ज माफी का लाभ नहीं मिल पाता है।

चुनावी साल है तो राजनीति भी होगी। होनी भी चाहिए, लेकिन ऐसी योजनाओं में अवरोध पैदा करना घातक हो सकता है। यह बात इसलिए, क्योंकि गैर भाजपा शासित राज्यों से केंद्र को आंकड़े देने में आना-कानी हो रही है। जायद फसल का सीजन है और किसानों को यह किस्त न मिल पाए तो नुकसान संबंधित सरकारों को भी उठाना पड़ेगा। पांच लाख रुपये तक मुफ्त इलाज की आयुष्मान योजना में तो राज्यों को भी हिस्सा चुकाना पड़ता है और इस लिहाज से कई गैर भाजपा शासित राज्यों ने हाथ खींच लिए हैं, लेकिन पीएम किसान सम्मान योजना का पैसा तो पूरी तरह केंद्र से जाना है। याद रहे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक वक्त मनरेगा को संप्रग काल का खंडहर करार दिया था, लेकिन उन्होंने इसे आगे बढ़ने से नहीं रोका। यह राजनीतिक लिहाज से भी उचित नहीं था। किसी भी सरकार के लिए जनोपयोगी कल्याणकारी योजना के आड़े आना खतरनाक है।

(लेखक दैनिक जागरण के राष्ट्रीय ब्यूरो प्रमुख हैं)

response@jagran.com

## ऊर्जा

### समृद्धि

जीवन के दो रूप हैं-एक ओर अमीरों की ऊंची अट्टालिकाएं, दूसरी ओर फुटपाथों पर रेंगती गरीबी। एक ओर वैभव ने व्यक्ति को विलासिता दी और विलासिता ने व्यक्ति के भीतर क्रूरता की प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया तो दूसरी ओर गरीबी तथा अभावों की त्रासदी ने उसके भीतर विद्रोह की आग जला दी। वह प्रतिशोध में तपने लगा, अनेक बुराइयां बिन बुलाए घर आ गईं। नीति और निष्ठा के केंद्र बदलने लगे। आस्था की नींव कमजोर पड़ने लगी। अर्थ की अंधी दौड़ ने व्यक्ति को संग्रह, सुविधा, सुख, विलास और स्वार्थ से जोड़ दिया। समस्या सामने आई-पदार्थ कम, उपभोक्ता ज्यादा। व्यक्तिवादी मनोवृत्ति जागी। स्वार्थों के संघर्ष में अन्याय और शोषण होने लगा। हर व्यक्ति अकेला पड़ गया। जीवन आदर्श थम से गए।

समृद्धि हर युग का सपना है और जीवन की अनिवार्यता में इसे शामिल भी किया जाता रहा है। सापेक्ष दृष्टि से सोचें तो समृद्धि बुरी नहीं है, लेकिन बुरी है वह मानसिकता जिसमें अधिसंख्य लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं को लील कर कुछ लोगों को उनके शोषण से अर्जित वैभव पर प्रतिष्ठित किया जाता है। खराब है समृद्धि का वह वैभव प्रदर्शन जिसमें अपराधों को पनपने का खुला अवसर मिलता है। अपनों के बीच संबंधों में कड़वाहट आती है। ऊंच-नीच की भेद-रेखा खींचती है। आवश्यकता से ज्यादा संग्रह की प्रतिस्पर्धा होती है। अनियंत्रित मांग और इंद्रिय असंयम व्यक्ति को स्वच्छंद बना देता है। हिंसा और परिग्रह के संस्कार जागते हैं। समृद्धि के साथ व्यक्ति की आदत, अभिरुचि, आकांक्षा, बहुत कुछ अपसंस्कृति से प्रभावित होकर गलत दिशा पकड़ लेती हैं। तमाम व्यक्ति फैशन की चकाचौंध में झूठे प्रदर्शन करते हैं। समृद्धि की तथाकथित आधुनिक जीवनशैली ने जीवन मूल्यों के प्रति अनास्था को पनपाया है।

समृद्ध-जीवन किसी-न-किसी 'ध्येय' को धारण करे और उस ध्येय को पाने के लिए 'निष्ठा' का पाल बांधे, तभी हम समृद्धि को अभिशाप नहीं, बल्कि वरदान बना सकेंगे। तभी इसे शक्ति का रूप दे सकेंगे। भले हमारे पास कार, कोठी और कुर्सी न हो, लेकिन चारित्रिक गुणों की काबिलियत अवश्य हो, क्योंकि इसी के बल पर हम अपने आपको महाशक्तिशाली बना सकेंगे।

ललित गर्ग

# ई-वोटिंग समय की मांग

देवेंद्रराज सुथार

**मतदान के दिन प्रवासी लोग भी अपने निवास स्थल से दूर रहकर अपने वोट का इस्तेमाल कर सकें इसके लिए विकल्प तलाशने चाहिए**

हमारे देश में मतदान को लेकर तमाम तरह के जागरूकता कार्यक्रम संचालित होने के बाद भी लोकसभा और विधानसभाओं के चुनावों में करीब 60-70 फीसद ही वोट पड़ते हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर सभी लोग वोट क्यों नहीं करते हैं। प्रायः इसका कारण या तो लोगों को कोई प्रतिनिधि पसंद नहीं आया या फिर उनका चुनाव से विश्वास ही उठ गया समझा जाता है, लेकिन ऐसा होने के पीछे अन्य कारण भी होते हैं जिन पर हमारा ध्यान नहीं जाता है। जहां तक लोगों द्वारा नापसंद जाहिर करने का सवाल है तो चुनाव आयोग ने उन्हें नोटा का विकल्प पहले ही दे रखा है तो फिर कुछ लोग वोट देने को लेकर इतने उदासीन क्यों बने रहते हैं। दरअसल कई लोगों को वोट के दिन मतदान केंद्र पर जाना, अपना नंबर आने के लिए लंबी-लंबी कतारों में खड़े रहना, इंतजार करना बोरियत भरा काम लगता है। वहीं कई लोग अपने रोजगार और नौकरी के सिलसिले में अपने निवास स्थान से बाहर रहते हैं और वोट वाले दिन उनका अवकाश लेकर आना संभव नहीं होता है।

इस तरह एक बड़ी संख्या लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लेने के लिए इच्छुक होने के बाद भी इस पर्व से बाहर रह जाती है। निःसंदेह लोकतंत्र के लिए इतनी बड़ी संख्या का मतदान प्रक्रिया में भाग नहीं लेना उचित नहीं है। यह बात देश के चुनाव आयोग एवं सरकार की चिंताओं में प्रमुखता से शामिल होनी चाहिए। वोट के दिन प्रवासी लोग भी अपने निवास स्थल से दूर रहकर अपने वोट का इस्तेमाल कर सकें इसके लिए विकल्प तलाशने चाहिए। अब समय आ गया है कि हमारे देश में भी ऑनलाइन वोटिंग यानी ई वोटिंग को लेकर चर्चा हो और इस प्रणाली को अपनाने के लिए एक राय बने। इसके सकारात्मक पक्षों के साथ ही नकारात्मक पक्षों पर विचार कर उसकी संभावना को साकार करने के प्रयत्न किए जाएं। हालांकि ऑनलाइन वोटिंग कोई अभूतपूर्व विचार नहीं है। आज दुनिया भर के कई विकसित लोकतंत्र ई-वोटिंग के विकल्प पर विचार कर रहे हैं। कई देशों में तो ई-वोटिंग शुरू भी हो चुकी है। इंटरनेट की बढ़ती लोकप्रियता ने ई-डेमोक्रेसी के विचार को जन्म दिया है। कई अन्य बदलावों के अलावा उन्होंने इंटरनेट को भी तेज विकास और परिवर्तन का जरिया बनाया है। वर्तमान समय में दुनिया के 14 देशों में यह सुविधा किसी न किसी रूप में या अस्थायी स्वरूप में मौजूद है। एस्टोनिया पूरी तरह से ऑनलाइन वोटिंग प्रणाली अपनाने वाला देश बन चुका है।

आज जब हमारा देश हर क्षेत्र में डिजिटल क्रांति के सपने को साकार कर रहा है तो क्यों न वोटिंग प्रणाली को भी पूरी तरह से डिजिटल एवं मतदाताओं के लिए आसान कर दी जाए। यदि ऐसा होता है तो हमारा वोट प्रतिशत काफी हद तक बढ़ सकता है और साथ ही यह चुनाव के खर्च और भारी तामझाम को कम कर सकता है। यह सही है कि भारत जैसे बड़ी आबादी वाले देश के लिए यह सब इतना आसान भी नहीं होगा, परंतु कोशिश पर दुनिया कायम है। इसके लिए हमें इंटरनेट के विस्तार के साथ ही अच्छी और भरोसेमंद सेवा उपलब्ध करवानी होगी एवं डिजिटल विषमता की समस्या का भी हल निकालना होगा।

(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

## मेलबाक्स

### आतंकवाद से प्रभावित हो रहा विकास

जेकेएस परिहार ने अपने आलेख 'आतंक पर अंकुश का स्थायी उपाय' के माध्यम से कश्मीर में आतंकवाद के कारण पनप रहे प्रतिकूल माहौल पर चिंता व्यक्त की है। यह सर्वविदित है कि भारत विश्व के सभी देशों के साथ-साथ पाकिस्तान के साथ भी मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करने का सार्थक प्रयास करता रहा है, परंतु पाक ऐसा देश है, जिसने सदैव भारत के साथ धोखाधड़ी की है। वह बेवजह भारत के उस हिस्से को हथियाने का प्रयास करता रहा है, जो उसका है ही नहीं। इसी वजह से वह आतंकवाद को बढ़ावा देकर भारत से दुश्मनी मोल लेता रहा है। आखिर ऐसा कब तक चलता रहेगा? कब तक हमारे देश के जवान शहीद होते रहेंगे। अब तो धरती मां भी रोने लगी हैं और मां को कष्ट पहुंचाना उचित नहीं होता। पाकिस्तान को यह समझना चाहिए कि वह आतंकवाद रूपी अराजकता को अंजाम देकर श्रेय का हकदार नहीं, अपितु अशांति का प्रतीक बनता जा रहा है। गौरतलब है कि आतंक से किसी भी देश का भला नहीं हो सका है और न ही उसका सर्वांगीण विकास। इसलिए पाकिस्तान को आतंकवाद रूपी दंश को समाप्त करके भारत से मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करके दोनों देशों के विकास के बारे में सोचना चाहिए तथा विश्व के अन्य देशों के समक्ष मिसाल बनकर अपनी साफ-सुथरी तस्वीर पेश करने का सार्थक प्रयास करना चाहिए। इसी में उसकी भलाई है।

सौरभ पाठक, ग्रेटर नोएडा

### महिला आइपीएल पर विचार

आइपीएल को भारत में किसी क्रिकेट टूर्नामेंट की तरह नहीं अपितु एक त्योहार की तरह समझा जाता है। महिलाओं ने भी क्रिकेट में अपनी क्षमता और काबिलियत को दर्शाया है। इसके मद्देनजर इस साल होने वाले आइपीएल के दौरान महिला आइपीएल का छोटा टूर्नामेंट करवाने पर प्रशासकों द्वारा विचार किया जा रहा है। महिला आइपीएल पूरी तरह से आयोजित न हो पाने का सबसे बड़ा कारण पैसों की तंगी और किसी भी टीम के लिए बोली लगाने वाले खरीदार न मिल पाना बताया जा रहा है। महिला क्रिकेट को मजबूती देने, साथ ही अधिक महिलाओं को क्रिकेट में बढ़ावा देने के लिए महिला आइपीएल का होना बेहद जरूरी है। बीसीसीआइ को इस पर ज्यादा गंभीरता से विचार करना चाहिए ताकि युवा लड़कियों को भी अपनी क्षमता को दिखाने का मंच मिल सके।

निशांत रावत, दिल्ली विवि

### अवैध शराब पर लगे रोक

देश में आए दिन किसी ना किसी राज्य में जहरीली शराब पीने से लोगों की जान चली जाती है। जब कोई बड़ी घटना होती है तब जांच कमेटियां बना दी जाती हैं, उसके बाद सब कुछ सामान्य हो जाता है। अवैध शराब का धंधा फिर वैसे ही चलने लगता है। केंद्र और राज्य सरकारें जहरीली शराब के विरुद्ध ठोस कार्रवाई करें।

विजय कुमार धनिया, नई दिल्ली

### मेहनत का विकल्प नहीं

देश में 10वीं एवं 12वीं की परीक्षा का दौर चल रहा है। ऐसे में विद्यार्थियों का पढ़ाई पर ध्यान फोकस करना और अतिरिक्त समय अध्ययन के लिए निकालना आवश्यक है। पूरे सत्र संजीदगी के साथ पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए परीक्षा तनाव पैदा नहीं करती है, परंतु जिन छात्रों की तैयारी अच्छी नहीं होती है वे शॉर्टकट तरीके अपनाने की कोशिश करते हैं, यह अनुचित है। पढ़ाई या कोई भी महत्वपूर्ण कार्य हो सबमें मन, चित्त की एकाग्रता परम आवश्यक है। वास्तव में मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। यह बात सभी बच्चों को समझनी चाहिए।

lalit.mahalkari@gmail.com

### अब रियायत नहीं

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का पीएम मोदी से एक और अवसर दिए जाने की मांग करना नाटक है। पाकिस्तान की नीयत कभी साफ नहीं रही है। इमरान खान की कोशिश है कि किसी भी तरह से भारत के अंदर जो प्रतिशोध की ज्वाला धधक रही है उसको ठंडा किया जाए। भारत की कड़ी कार्रवाई से भयभीत पाकिस्तान की सरकार ने यह चाल चली है। अब पाकिस्तान को किसी भी तरह की कोई भी रियायत देने की जरूरत नहीं है। भारत सरकार को अब सिर्फ और सिर्फ कार्र